CONTENTS

Fifteenth Series, Vol.V. Third Session, 2009/1931 (Saka)
No.3, Monday, November 23, 2009/Agrahayana 2, 1931 (Saka)

SUBJECT	PAGES
SUBMISSION BY MEMBERS	
RE: Reported leakage of Librahan Commission Report	**2-8**
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
***Starred Question Nos.41**	**10-18**
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.42-60	**19-76**
Unstarred Question Nos.457-671	**77-454**

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **456-458**

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE **459**
150th Report

STATEMENT BY MINISTER
Jawahar Lal Nehru National Solar Mission – "Solar India" **460-462**
Dr. Farooq Abdullah

ELECTION TO COMMITTEE
Central Advisory Board of Archaeology **463**

CIVIL DEFENCE (AMENDMENT) BILL,2009 **464**

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

6th Report **464**

MATTERS UNDER RULE 377 **466-473**

(i) Need to provide funds from the Railway grants for the maintenance of civic amenities in the railway zone of Mughalsarai Railway Division, Uttar Pradesh

Shri Ram Kishun 466

(ii) Need to increase the assistance rate of Calamity Relief Fund to Orissa

Shri B. Mahtab 467

(iii) Need to set up an Indian Institute of Technology in Kerala

Shri M.B. Rajesh 468

(iv) Need to repair the breached canal 'Kanniyamadhagu' in Tenkasi Parliamentary Constituency, Tamil Nadu

Shri P. Lingam 469

(v) Need to waive off the farm loan taken by farmers whose crops have been damaged due to drought conditions in Orissa

Shri Amarnath Pradhan 470

(vi) Need for doubling up of railway line between Kharagpur and Gokulpur via Giri Maidan in South Eastern Railways

Shri Prabodh Panda 471

(vii) Need to increase funds provided under Members of Parliament Local Area Development Scheme

Shri Kaushalendra Kumar 472

(viii) Need to ensure proper monitoring of financial package released for distressed farmers of Vidarbha region in Maharasthra

Shri Datta Meghe 473

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 474

Member-wise Index to Unstarred Questions 475-478

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 479

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 480

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Franciso Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, November 23, 2009/ Agrahayana 2,1931 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

SUBMISSION BY MEMBERS\

RE : Reported leakage of Librahan Commission

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, आज नेता प्रतिपक्ष की तरफ से प्रश्नकाल स्थगन का एक नोटिस दिया गया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि सबसे पहले उन्हें अपनी बात कहने की इजाजत दें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुझे नेता प्रतिपक्ष से प्रश्नकाल के निलंबन के लिए सूचना मिली है।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : लिब्राहन कमीशन के बारे में आज मैंने जो इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा, यह लीकेज क्यों हुआ? इसे बाकायदा सदन के पटल पर रखना चाहिए था। अध्यक्ष महोदया, ये परंपरायें हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं उसकी अनुमति नहीं दे रही हूं, क्योंकि वह नियम 388 के अनुरूप नहीं है, किंतु मैं नेता प्रतिपक्ष को संक्षेप में अपनी बात कहने के लिए अनुमति दे रही हूं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : वह आप ही की बात कह रहे हैं, इनकी बात आने दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है कि इस विषय पर भी कभी आपके कक्ष में बैठकर यह तय किया जाए कि किन-किन विषयों पर उचित रूप से प्रश्नोत्तरकाल स्थगित किया जा सकता है या इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जा सकता है। मैं आपका आभारी हूं कि चाहे आपने मेरा प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया, लेकिन मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति दी। मुझे जहां तक स्मरण आता है, मैंने जीवन में कभी पहले प्रश्नोत्तरकाल स्थगित करने की प्रक्रिया का उपयोग करने की कोशिश नहीं की। पहली बार मैंने नोटिस दिया है।

आज प्रातः काल जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस देखा तो मैं हैरान हुआ कि अभी तक तो यह रिपोर्ट सदन के सामने भी नहीं रखी गयी, सदन को भी नहीं बतायी गयी, तो इंडियन एक्सप्रेस को किसने बतायी और क्यों बतायी? मेरे एक साथी ने 'इंडियन एक्सप्रेस' के एडीटर से सीधे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कह सकता हूं कि यह ऑथेन्टिक है। इसमें कोई तथ्य हमने कपोल-कल्पित करके छापा हो, ऐसा नहीं है। मैं नहीं जानता हूं। मैं आश्चर्यचकित हूं। अगर कोई यह कहता है कि आडवाणी अयोध्या के उस अवसर पर, लोगों को संग्रहित करके वहां पर लाये, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां आए, इसीलिए यह घटना हो गयी। कोई कह सकता था, मैं अपेक्षा करता था कि शायद कोई कहेगा। इसमें इन्डाइटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें दो बातें कही गयी हैं। ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदया, आपने मुझे अनुमति दी है। ...(व्यवधान) मैं जीवन में पहली बार इस प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं? ...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): लीडर आफ अपोजीशन बोल रहे हैं, लीडर आफ हाउस बोलेंगे, क्या तब भी ऐसा करेंगे? ...(व्यवधान) आप बताइए, क्या व्यवस्था का प्रश्न है? ...(व्यवधान) कौन सी व्यवस्था का प्रश्न है? किस नियम के तहत आपका प्रश्न है? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उनका प्वाइंट आफ आर्डर है।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : यह डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप किस नियम के तहत इसे उठा रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप मुझे बोलने दीजिए। किस नियम के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं? आप वह नियम बताइए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, मैं आपके माध्यम से व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप नियम बताइए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, क्या सदन में समाचार पत्रों का संज्ञान लिया जाएगा? अगर समाचार पत्र में है, ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप नियम बताइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप नियम बताइए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इन्हें कोई नियम मालूम नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप नियम बताइए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं आपकी अनुमति से चाहता हूं कि क्या समाचार पत्रों का संज्ञान लिया जाएगा? समाचार पत्र क्या आप सदन में ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अगर आप नियम नहीं बता रहे हैं, तो आप अपना स्थान ग्रहण करिए। आप नियम बताइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह कोई व्यवस्था का उल्लंघन नहीं है। यह स्वयं व्यवस्था का उल्लंघन है। ...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : धन्यवाद। सम्मानित सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि वह कतरन देकर ही उसके आधार पर मैंने प्रॉपर परमीशन मांगी है, क्योंकि I was shocked to see this report.

जिस रिपोर्ट में मेरे वरिष्ठ नेता और काफी समय से अस्वस्थ चल रहे वाजपेयी जी को भी इनडाइट करने की बात कही गई है।...(व्यवधान) मुझे इनडाइट करते तो मैंने कहा कि मैं उसकी चुनौती को स्वीकार करता, चुनौती मानता। हवाला में मुझे इनडाइट करने की कोशिश की, मैंने चुनौती मानी। मेरा इनडाइटमैंट होता, मेरी पार्टी का इनडाइटमैंट होता, समझ में आता है, लेकिन वाजपेयी जी का उल्लेख देखकर मुझे लगा कि मेरा कर्तव्य बन जाता है कि जिनके नेतृत्व में मैंने जीवनभर राजनीति में काम किया, उनके खिलाफ, उनकी आज की अवस्था में कोई इस प्रकार की बात कहे और कही गई है। मैं इसलिए उसके बारे में डिटेल में नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि यह रिपोर्ट सरकार को जून के महीने में दी गई और जून के बाद आज नवम्बर का महीना पूरा होने को आया है, बीच में एक सैशन हो चुका है, उस समय गृह मंत्री जी ने यह रिपोर्ट सदन के सामने नहीं रखी। आज दूसरा सैशन शुरू हुए भी दो-तीन दिन हो गए हैं। हममें से बहुत सारे लोग समझते थे कि शायद पहले ही दिन यह रिपोर्ट रखी जाएगी, लेकिन नहीं रखी गई, दूसरे दिन नहीं रखी गई। आज तीसरा दिन है तो अचानक हम अखबार में मोटे तौर पर इस प्रकार की खबर

देखते हैं और एडीटर कहते हैं कि यह ऑथैंटिक रिपोर्ट है। उसमें थोड़े-बहुत शब्द बदले होंगे, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद एक दिन का भी विलंब करने का अधिकार सरकार को नहीं है, तुरंत रखनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि यह रिपोर्ट ज्यों की त्यों आज ही, सदन इसके बाद कोई दूसरी कार्यवाही न करे, इस रिपोर्ट को यहां पर रखने की मुझे इजाजत चाहिए। मैं दूसरी कोई मांग नहीं कर रहा हूं, मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि अगर यह बात सही है जो इसमें लिखी है, तो यह दोनों बातें सरासर असत्य हैं, मैटिकुलसली प्लैंड। कोई षडयंत्र नहीं था, कोई योजना नहीं थी, यह घटना हुई जिस घटना के बारे में स्वयं लिब्रहान कमीशन के सामने कहा। मैंने उसके बाद तुरंत लिखा हुआ है कि मेरे लिए एक बहुत दुखद दिन था, "It is the saddest day of my life." यह मैंने स्वयं लिब्रहान कमीशन के सामने कहा। उसकी एवीडैंस में भी आएगा। जहां तक मैंने देखा है कि इस रिपोर्ट में भी उसका थोड़ा सा उल्लेख है। लेकिन मोटे तौर पर मेरी मांग है कि आज बिना दूसरी कार्यवाही किए हुए गृह मंत्री जी इस सदन में वचन दें कि मैं तुरंत इस रिपोर्ट को लाकर सदन के सामने रखूंगा।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : वर्ना यह धारावाहिक चलता रहेगा, टू बी कंटीन्यूड है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस रिपोर्ट के नीचे लिखा हुआ है 'to be continued'. इस रिपोर्ट को उन्होंने इतना ऑथैंटिक माना कि वे इसे सीरियली देने को तैयार हैं, एक-एक हिस्सा करके, धारावाहिक करके देने को तैयार हैं। इस प्रकार की रिपोर्ट इस प्रकार अखबारों में छपती रहे, लीकेज होती रहे, It is a breach of privilege of the House, but that is a different matter. I have not taken recourse to the Privilege Motion, but I have sought from the Government immediate placing of this Report on the Table of the House. Personally, I am proud of my association with the Ayodhya Movement. I was distressed by the demolition of that structure, but so far as the Movement is concerned, मैं समझता हूं कि मेरे जीवन में मेरा अयोध्या मूवमैंट के साथ जुड़ना और वहां पर जनता की इच्छा के अनुसार उस स्थान पर एक भव्य राम मंदिर बने, यह मेरे जीवन की साध है और जब तक यह साध पूरी नहीं होगी, मैं इसके लिए कार्य करता रहूंगा। आज वहां पर एक मंदिर बना हुआ है और कुछ नहीं है, मंदिर ही है। लेकिन वह मंदिर जिस रूप में है, वह कोई भगवान रामचन्द्र के जन्म स्थान के अनुरूप नहीं है। मैं चाहूंगा कि वैसा ही एक भव्य मंदिर बने। यह मेरे मन की इच्छा है। आज गृह मंत्री जी से मेरी मांग है कि वह बिना अधिक विलंब के इस रिपोर्ट को सदन के सामने रखें जिससे हमें समझ में आए कि लिब्रहान कमीशन ने क्या कहा है। मेरी कम से कम उनके सामने जितनी एवीडैंस की रिपोर्ट हो गई, निश्चित रूप से दस दिन तक मैंने

लिब्रहान कमीशन के सामने अपना बयान दिया, अपना विचार रखा, अयोध्या मूवमैंट के बारे में कहा। डिमॉलिशन मैं कभी एक्सपैक्ट नहीं करता था, डिमॉलिशन जिस प्रकार हुआ, मैं आपको कह सकता हूं कि वहां पर जितने लोग थे, वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के थे, विश्व हिन्दू परिषद के थे, बीजेपी के थे।

सबने पूरी कोशिश की कि जितने लोग उसे तोड़ रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, वे ऐसा न करें। विश्व हिन्दू परिषद् के सबसे बड़े नेता श्री अशोक सिंघल को उन लोगों द्वारा मैन हैंडल किया गया। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं कहना। मैं एक बार फिर गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे लिब्राहन रिपोर्ट सदन के सामने रखें। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बहुत-बहुत धन्यवाद। मुलायम सिंह जी आपको क्या कहना है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं और नेता सदन भी बैठे हैं। …(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): आप उन्हें बोलने दीजिए। …(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: वे जरूर बोलें। …(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया ने मुझे बोलने का टाइम दिया है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उन्होंने यह मांग कर दी है, इसलिए आप बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट सदन के चलते लीक होना मैं अच्छा नहीं मानता हूं। लेकिन जहां तक नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनका सौभाग्य है, तो मेरा भी सौभाग्य है कि इनका और हमारा टकराव इसी इश्यू पर हुआ। वह टकराव मामूली नहीं हुआ। उस समय पूरे देश में ऐसी आग लगी थी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह लिब्रहान कमीशन 16 साल पहले गठित किया गया, जिसे इसी सरकार ने गठित किया। अब हालत यह है कि उस समय जो बच्चा था, वह अब जवान हो गया, जो जवान था, वह बूढ़ा हो गया और जो बूढ़ा था, वह मर गया, लेकिन लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट अभी तक सदन के सामने नहीं आयी। आखिर इसकी क्या वजह है? इसमें सरकार की भी रूचि है। एक रिलायंस कम्पनी है। उसकी रोजाना सुनवाई हो रही है, रोजाना पैरवी हो रही है। आखिर लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट को यहां पर रखकर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं। अगर रिपोर्ट लीक हुई है, तो वह कहां से हुई है और अगर लीकेज हो गयी है, तो मैं भी चाहता

हूं, मैं प्रतिपक्ष के नेता की बात से सहमत हूं कि सदन तब चले जब लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट यहां रखी जाये। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : बिल्कुल ठीक है, सदन तब चलेगा जब रिपोर्ट यहां पेश होगी।

श्री मुलायम सिंह यादव : इस मामले में देश को कन्फ्यूजन में नही रखना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं। धीरे-धीरे वही स्थिति आ सकती है, जो वर्ष 1990 से लेकर 1992 तक हुई। उस समय दंगे हुए जिसमें जानें गयीं, आग लगी आदि सब कुछ हुआ। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार यह जिम्मेदारी ले। आडवाणी साहब, आपका सौभाग्य है, तो मेरा भी सौभाग्य है कि हम आपके बीच टकराये और हमने मस्जिद की हिफाजत की। हमारा यह मत अभी तक साफ है कि न्यायालय जो भी फैसला करे, उसे हम स्वीकार करेंगे। अब वह फैसला चाहे मंदिर के पक्ष में हो या मस्जिद के पक्ष में हो। हमारा यही इश्यू था और इसी को लेकर हम चले थे। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ा, न चाहते हुए हमें कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी जिसमें लोगों की जानें भी गयीं, बहुत सी सम्पति बर्बाद हुई। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा अब इस मुद्दे को ज्यादा लम्बा खींचना उचित नहीं है। हम संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि सदन में ..(व्यवधान) गृह मंत्री जी हैं, तो तत्काल खड़े होकर बतायें। ...(व्यवधान) आप इस रिपोर्ट को आज ही सदन में रखिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप सब शांत हो जाइये।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आज ही रिपोर्ट सदन में रखिए। हम तो कह रहे हैं कि अभी रखिए। सदन तब तक के लिए स्थगित किया जाए। रिपोर्ट सदन में लायी जाये। हम पूछना चाहते हैं कि रिपोर्ट यहां लाने में देर क्यों हो रही है? हम चाहते हैं कि लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट तुरंत यहां रखी जाये।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट काफी दिन से लंबित है। इसे पहले ही सदन में लाना चाहिए था। लेकिन आज चर्चा दो सौभाग्यशाली लोगों के बीच में हो रही है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट तत्काल यहां पर आ जानी चाहिए। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि बिना संसद में रिपोर्ट आये हुए लीक हो जाना इससे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए इन पर सारी जिम्मेदारी है। इनको पहले स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कैसे यह रिपोर्ट लीक हुई? मैं बस यही कहना चाहता हूं।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, the Liberhan Commission is the longest Commission in our country. So many times, extensions have been given. We have been demanding since long that the Liberhan Commission's

Report should be brought before the House. When after the long 17 years, the Report was submitted to the Government in the last session, a demand was raised that the Report should be placed on the Table of the House.

When the entire nation is debating this and the report is selectively being leaked to the Press, why is the report not being placed before the House? Madam, when we demanded in the last Session, we were told that the report would be brought before Parliament along with the Action Taken Report. Our demand is that the Liberhan Commission Report along with the ATR be laid on the Table of the House today itself.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Madam, this is no doubt a matter of concern for all of us. The precedent in the House is that these reports are first brought before Parliament. Once a report is placed on the Table of the House, there is no harm in it being released to the press. It is a privilege of the House. As has been stated here, before being placed on the Table of the House the report has been leaked to the press. I do not know how far it is true. If it is true, the hon. Home Minister, who is present here, may state the facts. I demand that this report be placed on the Table of the House immediately. I also demand that the Home Minister do clarify whether this report has been leaked to the press or not.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी :महोदया, एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि आपने कहा है कि यह बताओ कि लीकेज हुआ है या नहीं, इसमें रेफरेंस अगर किसी का है, तो होम मिनिस्ट्री सोर्सेज का ही है। Whether it is correct or not I do not know. I would like the Home Minister to clarify that. The newspaper report says, "Sources in the Union Home Ministry have confirmed to *The Indian Express* that the report is also severely critical of many Muslim leaders representing organizations such as Babri …". It further says, "The Home Ministry, which is giving final touches to the action taken report (ATR), intends to table the ATR in Parliament along with the report of the Commission during the ongoing Winter Session". So, the two references in this report are also to the Home Ministry.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam Speaker, Government has noticed that a newspaper has carried a news story today relating to the report of the Liberhan Commission. The Liberhan Commission submitted its report on June 30, 2009. Government is required to lay the report on the Table of both Houses of Parliament together with an Action Taken Report within six months from that date. Government has already announced its intention to lay the report together with an ATR before Parliament in the Winter Session. Given the Government's intention to lay the report within the stipulated time, it is unfortunate that a newspaper has published what purports to be the contents of the report. For reasons that are obvious, I refrain from commenting on the correctness or otherwise of the contents of the news story. I can assure the House, Madam, that there is only one copy of the Liberhan Report with the Ministry of Home Affairs and it is in safe custody, and no one from the Ministry of Home Affairs has spoken to any journalist about the report. I reiterate Government's intention to lay the report before Parliament along with an ATR in the current Session.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैडम, सरकार का जवाब सही नहीं है। हमारा यह आरोप है कि यह रिपोर्ट सरकार की ओर से लीक कराई गयी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। कृपया प्रश्नकाल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : महोदया, इस रिपोर्ट को पहले सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए था। यह सदन के विशेषाधिकार का सवाल है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। कृपया प्रश्नकाल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

11.04 hrs

At this stage, Dr. Sushant Rajan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

(Q. No. 41)

MADAM SPEAKER : Shri Ghanshyam Anuragi, Q. No.41.

Nothing but Questions and Answers will go on record.

*(Interruptions) ...**

MADAM SPEAKER: Shri Anuragi, please put your first Supplementary.

...(व्यवधान)

श्री घनश्याम अनुरागी : अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में आतंक, चोरी, लूट आदि घटनाओं को देखते हुए सरकार को साल में 365 दिन रोजगार देना चाहिए।...(व्यवधान) ऐसा नहीं होने पर देश में बेरोजगार लोग आतंक, लूटपाट और चोरी जैसे कृत्यों की ओर उन्मुख हो रहे हैं इसलिए देश के बेरोजगारों को रोजगार देने की नितांत आवश्यकता है। सरकार जब तक सभी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती, तब तक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार कब तक बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को देगी और क्या सरकार इस पर विचार कर रही है?...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: According to Employment Market Information Programme of the Ministry of Labour & Employment, employment growth in organized sector, public and private sectors combined has increased from 264.43 lakh in 2004 to 272.76 lakh in 2007, registering an average rate of growth of 1.05 per cent per annum. The corresponding growth of employment in public sector has shown a negative growth of (-) 0.36 per cent per annum whereas the private sector has recorded an average annual growth of 4.16 per cent per annum during the same period. State-wise employment in organized sector for the period 2004, 2005, 2006 and 2007 is given at Annex-I.

I placed the entire reply on the Table of the House.

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यो, कृपया बैठ जाएं। नेता प्रति पक्ष ने अपनी बात सदन में कही है। सदन में अन्य दलों के सदस्यों ने भी अपनी बात रखी और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है इसलिए अब प्रश्न काल चलने दें।

...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत हो जाएं। घनश्याम अनुरागी जी आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछें।

...(व्यवधान)

श्री घनश्याम अनुरागी : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में देश में 50 मिलियन के करीब रोजगार सृजित करने की बात कही है।...(व्यवधान) अभी तक कितने रोजगार सृजित किए गए हैं और कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है?...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Eleventh Five Year Plan aims at creating 58 million job opportunities and it is expected that there would be reduction in unemployment rate to 4.83 per cent on current daily status towards the end of the Plan period. Government have taken several steps to reduce unemployment rate. The focus is on productive employment at a faster pace in order to raise the incomes of masses of the rural population to bring about a general improvement in their living conditions. The job opportunities are likely to be created on account of growth in Gross Domestic Product (GDP), investment in infrastructure development, growth in exports, etc. The Government of India has also been implementing various employment generation programmes, such as, Swarana Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY); Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP); Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana(SGSY) and National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS).

The Government is implementing many programmes to create jobs in the country. Nearly five lakh more people have got employment. The Quarter July-Sep., 2009.

… (*Interruptions*)

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझसे रूल की बात कही है। ...(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने देश में जो राज्यवार ब्यौरा दिया है, उसमें खुद स्वीकार किया है कि जो हमारे सरकारी उपक्रम हैं, उनमें 1.76 परसेंट की वृद्धि हुई है और गैर-सरकारी उपक्रम में 4.16 परसेंट की वृद्धि हुई है। पिछले दिनों वैश्विक आर्थिक मंदीकरण के कारण जो रोजगार थे, उन रोजगारों में कंपनियों ने कितने लोगों की छटनी की है, क्या माननीय मंत्री जी उनकी संख्या इस सदन को उपलब्ध कराएंगे? मंदी के कारण कुछ कंपनियां बंद हुईं हैं और यह सवाल रोजगार से जुड़ा सवाल है,

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस वैश्विक मंदीकरण के कारण कितने लोगों को सरकारी या गैर-सरकारी कंपनियों ने बेरोजगार किया है? क्या मंत्री जी उसका ब्यौरा उपलब्ध कराएंगे?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सभापति महोदया जी, पूरी डिटेल तो इस समय हमारे पास नहीं है, हम अभी इतना ही कह सकते हैं कि जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में कटौती हो गयी है, उसका विवरण हमने अनैक्श्चर (1) और (2) में दिया है। इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के पूरे स्टैटिस्टिक्स हमने फर्निश किये हैं, जिन्हें वह अनैक्श्चर (1) और (2) में देख सकते हैं। … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER : The House stands adjourned to meet again at 12 O'Clock.

11.27 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Madam Speaker *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

12.01 ¼ hrs

At this stage, Shri Gopinath Munde and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

MADAM SPEAKER: Papers to be laid on the Table.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

PAPERS LAID ON THE TABLE

12.0 ½ hrs

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI MUKUL ROY): On behalf of Shri G.K. Vasan, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963:-

(i) G.S.R. 601(E) published in Gazette of India dated the 27th August, 2009 approving the Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009.

(ii) G.S.R. 766(E) published in Gazette of India dated the 20th October, 2009 approving the Kandla Port Employees (Retirement) Amendment Regulations, 2009.

(iii) G.S.R. 685(E) published in Gazette of India dated the 17th September, 2009 approving the Cochin Port Trust Employees (Retirement) Amendment Regulations, 2009.

(iv) G.S.R. 689(E) published in Gazette of India dated the 23th September, 2009 approving the Tuticorin Port Trust Employees (Retirement) Amendment Regulations, 2009.

(v) G.S.R. 684(E) published in Gazette of India dated the 17th September, 2009 approving the Madras Port Trust Employees' (Retirement) Amendment Regulations, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 758/15/09)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ANAND SHARMA): On behalf of Shri Jyotiraditya Madhavrao Scindia, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 49 of the Special Economic Zone Act, 2005:-

(i) Draft Notification No. F. No. C.3/9/2008-SEZ exempting setting up of offsite ATMs and general branches by banks in Special Economic Zones, not licensed as Offshore Banking Units; from the provisions of clause (u) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005, alongwith a Statement of Objects and Reasons and an Explanatory Notes.

(ii) Draft Notification No. F. No. D.6/12/2009-SEZ exempting Special Economic Zones from the requirement of obtaining distribution license, alongwith a Statement of Objects and Reasons and an Explanatory Notes.

(Placed in Library, See No. LT 759/15/09)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951:-

(i) The Newsprint Control (Amendment) Order, 2009 published in Notification No. S.O. 2155(E) in Gazette of India dated the 24th August, 2009.

(ii) The Newsprint Control (Amendment) Order, 2009 published in Notification No. S.O. 2156(E) in Gazette of India dated the 24th August, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 760/15/09)

(3) A copy of the Tea Board (Recruitment and Conditions of Service of Directors of Tea Promotion appointed by Government) Amendment Rules, 2007 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 443(E) in Gazette of India dated the 23rd June, 2009 under sub-section (3) of Section 49 of the Tea Act, 1953.

(Placed in Library, See No. LT 761/15/09)

(4) A copy of the Rubber (Amendment) Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 760(E) in Gazette of India dated the 16th October, 2009 under sub-section (3) of Section 25 of the Rubber Act, 1947.

(Placed in Library, See No. LT 762/15/09)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI GURUDAS KAMAT): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Telecommunications Consultants India Limited and the Department of Telecommunications for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 763/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI HARISH RAWAT): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Statement (Hindi and English versions) on ILO Convection No. 127 and Recommendation No. 128 (Maximum Weight).

(Placed in Library, See No. LT 764/15/09)

(2) A copy of the National Policy (Hindi and English versions) on HIV/AIDS and the World of Work.

(Placed in Library, See No. LT 765/15/09)

… (*Interruptions*)

12.01 hrs.

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
150th Report

SHRI MADAN LAL SHARMA (JAMMU): I beg to lay on the Table a copy of the One Hundred and Fiftieth Report (Hindi and English versions) on the National Commission for Heritage Sites Bill, 2009 of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture.

12.02 hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Jawahar Lal Nehru National Solar Mission – "Solar India"*

THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (DR. FAROOQ ABDULLAH): Madam Speaker, I beg to lay a statement on Jawahar Lal Nehru National Solar Mission – "Solar India".

I am happy to announce that the Government has approved a new policy on development of solar energy in the country by launching of the Jawaharlal Nehru National Solar Mission. This is a historic and transformational initiative of the UPA Government and I am proud to have the privilege of being assigned the task of overseeing its implementation. The Solar Mission is very much in line with the vision of modern India of Pandit Nehru, which has made India today, a leading nuclear and space power.

This Mission is one of the eight key National Missions which comprise India's National Action Plan on Climate Change. It has a twin objective - to contribute to India's long term energy security as well as its ecological security. We are living in a world of rapidly depleting fossil fuel resources; and access to conventional energy resources, such as oil, gas and coal, is becoming increasingly constrained. The rapid development and deployment of renewable energy is imperative in this context and in view of high solar radiation over the country solar energy provides a long term sustainable solution.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 766/15/09.

The Solar Mission recommends the implementation in 3 stages leading up to an installed capacity of 20,000 MW by the end of the 13th Five Year Plan in 2022. It is envisaged that as a result of rapid scale up as well as technological developments, the price of solar power will attain parity with grid power at the end of the Mission, enabling accelerated and large-scale expansion thereafter. During this time we expect many new ideas to emerge and technologies to become more efficient. Quite obviously, in order to set the stage for achieving this ambitious target, what we do in the next 3 to 4 years will be critical. Therefore, the Cabinet has approved setting up of 1,100 MW of grid solar power and 200 MW capacity of off-grid solar applications utilizing both solar thermal and photovoltaic technologies in the first phase of the Mission. In addition, Mission will also focus on R&D and HRD to develop and strengthen Indian skills and enhance indigenous content to make the Mission sustainable.

Mission will establish a single window investor-friendly mechanism, which reduces risk and at the same time, provides an attractive, predictable and sufficiently extended tariff for the purchase of solar power for the grid. The focal point, for the next 3 years, will be the NTPC Vidyut Vyapar Nigam (NWN), which is the power trading arm of the NTPC. Government will designate it for the purchase of solar power generated by independent solar power producers, at rates fixed by the Central Regulatory Electricity Commission and for a period specified by the latter. Government will provide equivalent MW of power from the unallocated quota of NTPC for bundling with solar power. The utilities will be able to account for purchase of solar power against their RPO obligations.

I wish to record my deep appreciation and grateful thanks to my senior colleague, Shinde Saheb, who as Minister of Power, has made this arrangement possible and has supported this Mission at every stage of its evolution.

The Mission also includes a major initiative for promoting rooftop solar PV applications. Solar tariff announced by the regulators will be applicable for such

installations. The power distribution companies will be involved in purchase of this power.

There are several off-grid solar applications which are already commercially viable or near viability, where rapid scale up is possible. This requires regulatory and incentive measures as well as an awareness campaign. Solar thermal heating applications, such as water heaters, fall in this category. Solar lighting systems for rural and remote areas are already being distributed commercially in several parts of the country. This is expected to help our rural masses.

The mission will have a very focused R&D programme which seeks to address the India-specific challenges in promoting solar energy. We have to pool available resources both human and financial to strengthen the existing scientific infrastructure in the country. We would involve various stakeholders in human resource development and other capacity building efforts. Mission will also accelerate the process of development of domestic industry in this sector.

I seek cooperation of members of the House to make Jawaharlal Nehru National Solar Mission a success, which will help establish India as one of the global leaders in Solar Energy.

12.03 ¼ hrs.

ELECTION TO COMMITTEE
Central Advisory Board of Archaeology

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): On behalf of Shri V. Narayanasamy, I beg to move:

> "That in pursuance of the provision in paragraph XVIII of the Government of India, Archaeological Survey of India, Resolution No. 9/2/2008-EE(CABA) dated 15th September, 2009, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves, to serve as members of the Central Advisory Board of Archaeology (CABA), subject to the other provisions of the said Resolution."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of the provision in paragraph XVII of the Government of India, Archaeological Survey of India, Resolution No. 9/2/2008-EE(CABA) dated 15th September, 2009, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves, to serve as members of the Central Advisory Board of Archaeology (CABA), subject to the other provisions of the said Resolution. "

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

12.03 ½ hrs.

CIVIL DEFENCE (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): On behalf of Shri P. Chidambaram, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Civil Defence Act, 1968.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Civil Defence Act, 1968."

The motion was adopted.

SHRI MULLAPALLY RAMACHANDRAN: I introduce the Bill.

12.03 ¾ hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
6th Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam Speaker, I beg to present the Sixth Report of the Business Advisory Committee.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 2, dated 23.11.09.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up Matters Under Rule 377.

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष जी, लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट लीक हुई है।...(व्यवधान) मेरा आरोप है कि वह रिपोर्ट सरकार ने लीक करवाई है और सरकार के अधिकृत सूत्रों से यह रिपोर्ट लीक हुई है। विपक्ष की जो एकजुटता गन्ना किसानों के मुद्दे पर बनी थी, वह सरकार को रास नहीं आ रही थी।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले बोल चुकी हैं। रिकार्ड में आपकी बात आ गई है।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज :हमारी सरकार से मांग है कि इस लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट को आज ही पेश कराया जाए।...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): उपाध्यक्ष जी, हाउस को एडजर्न करवा दीजिए क्योंकि गृह मंत्री जी ने जो कहा है, उसे ये सही नहीं मान रहे हैं। ...(व्यवधान)

14.01 hrs.

At this stage, Shri Gopinath Munda and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

14.01 ½ hrs.

MATTERS UNDER RULE 377*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters Under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise Matters Under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over slips at the Table of the House immediately. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table, the rest will be treated as lapsed.

(i) Need to provide funds from the Railway grants for the maintenance of civic amenities in the railway zone of Mughalsarai Railway Division, Uttar Pradesh

श्री रामकिशुन (चन्दौली): उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में स्थित रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत रेल कर्मचारियों/अधिकारियों/नागरिकों के कल्याण एवं अन्य नागरिक सुविधाओं हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा रेलवे सेटलमेंट बोर्ड का गठन किया गया था। इस रेलवे सेटलमेंट बोर्ड के द्वारा मुगलसराय रेलवे क्षेत्र में विकास कार्य गुणवत्ता के साथ किए जाते थे। रेलवे सेटलमेंट बोर्ड को उत्तर प्रदेश सरकार धन मुहैया कराती थी। बोर्ड के माध्यम से रेलवे क्षेत्र में स्थित आवासीय परिसर, सड़क, सीवर आदि के रख-रखाव के साथ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आदि जारी करने की सुविधा प्राप्त थी। लेकिन रेलवे की सिफारिश पर रेलवे सेटलमेंट बोर्ड को समाप्त करा दिया गया जिससे आज रेलवे क्षेत्र में स्थित आवासीय परिसर, सड़क, सीवर आदि की स्थिति दयनीय बनी हुई है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह की सुविधाएं मुगलसराय रेलवे क्षेत्र में रेलवे सेटलमेंट बोर्ड के द्वारा जिस गुणवत्ता के साथ उपलब्ध करायी जाती थी, उसकी क्षति पूर्ति के लिए रेलवे, मुगलसराय रेलवे क्षेत्र के विकास कार्य आदि की विशेष सुविधा हेतु बोर्ड के अनुरूप ही धन उपलब्ध कराकर अन्य कल्याणकारी योजना, सामाजिक सुविधाओं के साथ-साथ रेलवे क्षेत्र परिसर में स्थित दो-तीन सरोवर के घाट आदि का निर्माण एवं मरम्मती, रख-रखाव कार्य सुचारू रूप से कराये।

---

* Treated as laid on the Table.

(ii) Need to increase the assistance rate of Calamity Relief Fund to Orissa

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Orissa amounts of over 10 percent of paddy acreage and contributes about 7.5% of rice production in the country though hardly 30 percent of the cultivable land is under assured irrigation. But in this Kharif season Orissa is facing acute drought in many districts and farmers are in need of support. Presently, under the CRF norms, in the event of farmers suffering loss of more than 50% of the crop, assistance is provided at the rate of Rs.4000/- per hectare for areas under assured irrigation and only Rs. 3000/- per hectare for non-irrigated areas. This amount of assistance is very meagre and should atleast be increased to Rs. 10,000/- per hectare for irrigated and Rs. 5,000/- per hectare for non-irrigated areas. This will also necessitate increase in CRF corpus for the States including Orissa.

CRF assistance given to Orissa is not adequate. Even NCCF is not being provided to Orissa keeping the grave natural calamity in view. I urge upon the Government to increase the assistance rate of CRF at the earliest.

(iii) Need to set up an Indian Institute of Technology in Kerala

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): The establishment of an IIT is a long standing dream of the people of Kerala. The State Government has time and again informed the Central Government that Kerala is ready to render all facilities for the setting up of IIT. The Chief Minister has made representation to Hon'ble Prime Minister twice. The Prime Minister and the Central Government had assured that the Genuine demand of the State will be fulfilled. Even though eight new IITs were announced in the last Independence Day speech of Hon'ble Prime Minister, Kerala was again left out. Being a State which has achieved impressive achievements in the sphere of education, Kerala has every reason to demand an IIT. I urge upon the Government of India to fulfil its assurance of setting up an IIT in Kerala in this financial years itself.

(iv) Need to repair the breached canal 'Kanniyamadhagu' in Tenkasi Parliamentary Constituency, Tamil Nadu

SHRI P. LINGAM (TENKASI)**:** Kanniyamadhagu canal from Shenbagavalli river running between Tamil Nadu and Kerala in the western ghats situated in the Sivagiri taluk in my constituency breached in 1975. It has not been renovated till date. Irrigation potential of this canal benefitted about 25 thousand acres of land in cultivation in Sivagiri taluk, Sankaran Kovil taluk and Sathur taluk of my Tenkasi constituency. Apart from enhancing food production this water flow helped meeting drinking water shortage too.

The breached canal remains unattended causing great hardship to people in this area. The westward wasteful flow of Shenbagavalli waters into the Arabian sea has not been arrested as yet. The Government of Tamil Nadu has not been able to carry out repair works as the canal breach has occurred in the area that comes under the jurisdiction of Government of Kerala's Kattappanai PWD office in the Idukki district of Kerala. Also, the area is located in a Tiger Sanctuary. As the Government of Tamil Nadu is ready to spend money on the repair and renovation works, I urge upon the Union Government to intervene to help save the poor farmers of the Tenkasi constituency.

(v) Need to waive off the farm loan taken by farmers whose crops have been damaged due to drought conditions in Orissa

SHRI AMARNATH PRADHAN (SAMBALPUR): Agriculture is the main source of livelihood of the people in Western Orissa. It is the first ever incident in the post-independence era of Orissa that incidents of suicides by farmers have been reported in the district of Sambalpur. The deaths have been caused due to crop failure because of severe drought condition prevailing there. The death toll has reached to 10 in the entire State while 3 cases of death have been reported in the district of Sambalpur. I request Hon'ble Agriculture Minister to waive off the farm loans taken by farmers during Kharif crop period and send a Central team to assess the damage caused by the drought in the affected districts.

(vi) Need for doubling up of railway line between Kharagpur and Gokulpur via Giri Maidan in South Eastern Railways

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): The Railway track between Kharagpur and Gokulpur via Giri Maidan in South Eastern Railway is being operated on a single line. The total length of this stretch is about 13 Kms. About 50 Express trains and other passenger and goods trains including Rajdhani Express pass through this section. It is also an important route for connecting Haldia port with rest of the country. Moreover, with the constructions of second railway bridge over river Kansai, the volume of rail traffic will go up. The need to lay double track has, therefore, become the necessity. Already, a heavy traffic congestion has become a regular feature on this route.

I, therefore, urge upon the Government to undertake doubling of railway track on this stretch immediately besides making Giri Maidan Railway Station as a crossing point station.

(vii) Need to increase funds provided under Members of Parliament Local Area Development Scheme

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सरकार ने यह माना है कि एमपीलैड्स के तहत जो काम हुए हैं वो विकास की राह में मील का पत्थर है, वो रुट्र की सम्पत्ति है । दूसरी तरफ सरकार ने इसे दो करोड़ रूपये तक सीमित कर दिया है । निर्माण सामग्री का दाम और मजदूरी बढ़ जाने से सभी काम करवाना, आजकल ज्यादा बजट का हो गया है जो कि 2 करोड़ रूपये में संभव नहीं है । दूसरी तरफ सरकार मानती हे कि परिसीमन के बाद संसदीय क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप बदल गया है ।

सरकार यह भी मानती है कि मौद्रिक अवमूल्यन के बाद वास्तविक राशि का मूल्य केवल एक करोड़ छह हजार रूपये रह गया है जो कि बहुत ही कम है ।

कई संसदीय क्षेत्रों का भौगोलिक स्वरूप बदल गया है और काफी बड़ा भी हो गया है ।

चौदहवीं लोक सभा में मेरा संसदीय क्षेत्र नालन्दा जिसको मैं 15वीं लोक सभा में प्रतिनिधित्व करता हूँ, में केवल 6 विधान सभा क्षेत्र थे और अभी पूरा का पूरा नालन्दा जिला इसमें आ गया है जहां कि आठ विधान सभा क्षेत्र थे जिसकी आबादी लगभग 30 लाख है और यह देश के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्रों में एक है । यहां पर 20 ब्लॉक हैं । जनप्रतिनिधि के उपर काफी दबाव भी रहता है । ऐसे में 2 करोड़ रूपये से काम नहीं चलेगा ।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि आबादी के हिसाब से एवं बड़े संसदीय क्षेत्र के हिसाब से इसको बढ़ाया जाना चाहिए ।

(viii) Need to ensure proper monitoring of financial package released for distressed farmers of Vidarbha region in Maharasthra

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): महोदया, मैं सरकार का ध्यान महाराट्र के विदर्भ क्षेत्र में कृाि संकट के कारण किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं । पिछले सितम्बर महीने में 7 किसानों ने आत्महत्याएं कीं । इसके साथ राज्य में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 668 हो गई है । राज्य में पिछले पांच वर्ाों में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 7000 से अधिक हो गई है । यह स्थिति तब है जब विदर्भ के 6 जिलों के लिए 3,750 करोड़ रूपयों के पैकेजों की घोाणा की गई है । इन घो-ाणाओं के बावजूद यवतमाल में 1596, अमरावती में 1121, अकोला में 1016, वाशिम में 816, बुंलढ़ाना में 1077 और वर्धा में 495 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं । आत्महत्या करने वाले किसानों में अधिकतर बीटी कपास की फसल लेते हैं । लेकिन यह काफी महंगी होने तथा कपास के बाजार में उचित दाम नहीं मिलने के कारण किसानों पर अत्यधिक कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है जिसके कारण वे आत्महत्याएं कर रहे हैं ।

ऐसी स्थिति में मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जो पैकेज सरकार किसानों के लिए आवंटित करती है वे किसानों तक पहुंचते हैं या नहीं, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इस बात की जांच की जानी चाहिए कि सरकार द्वारा पैकेज देने के बाद भी किसान लगातार क्यों आत्महत्याएं कर रहे हैं ।

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, Tuesday, the 24th November, 2009 at 11 a.m.

14.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, November 24, 2009/Agrahayana 3, 1931 (Saka).